# सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-13 | 7 से 21 जुलाई, 2017 | मुख्य संपादक : कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये


## जीएसटी को घोर जनविरोधी करार देते हुए एसयूसीआई( सी ) ने किया तीव्र विरोध

### जोरदार प्रतिरोध आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान

**कोलकाता :** एसयूसीआई(सी)के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 29 जून 2017 को जारी प्रैस बयान में कहा कि गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स (जीएसटी) लागू करने का हम जोरदार विरोध करते हैं जो आम आदमी पर अप्रत्यक्ष करों का बड़ा भारी बोझ बढ़ा देगा, इससे लगभग जरूरत की सभी चीजों और सेवाओं के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी हो जाएगी। इस प्रकार इस व्यवस्था की महामारी के बढ़ते संकट को टालने के लिए निर्मम दमनकारी पूँजीवाद के द्वारा आये दिन लोगों पर ढायी जा रही आर्थिक क्रूरता का एक और दौर शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ, यह नये टैक्स का विधि-विधान पूँजीवादी निर्माताओं और कॉरपोरेट सेक्टरों को उनकी कर देनदारी में काफी हद तक छूट देगा। इस संदर्भ में यह दोहराने की जरूरत है कि पूँजीवाद में शुरू किये गये किसी आर्थिक सुधार का चरित्र और साथ ही साथ उसका निहितार्थ उस व्यवस्था से अलग-थलग रख कर नहीं समझा जा सकता। क्योंकि पूँजीपति वर्ग के समग्र हित में उठाया गया यह कदम केन्द्र सरकार के हाथों में टैक्स राजस्व के संकेन्द्रण और मुट्ठी में करने को सुविधाजनक बनाने में मददगार होगा और राज्य अपनी आर्थिक ताकत काफी हद तक खो बैठेंगे। यह आजादी के बाद से एक संघीय ढांचे के प्रमुख सिद्धान्त के तौर पर आपसी सहमति से केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के अब तक प्रचलित दस्तूर का सुस्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है। जाहिर है कि यह कदम केन्द्र के हाथों में आर्थिक शक्ति को और भी ज्यादा संकेन्द्रित करने का सबब बनेगा जो फिर देश को प्रशासनिक फासीवाद की तरफ धकेल देगा। यह तथ्य भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके नतीजे के तौर पर केन्द्र द्वारा नाजायज कराधान थोपे जाने के खिलाफ आन्दोलन गठित करना और भी कठिन हो जाएगा।

हम मेहनतकशों का आह्वान करते हैं कि जीएसटी को वापिस करवाने के लिए लामबंद हों और देशव्यापी जोरदार आन्दोलन खड़ा करें। जीएसटी के खिलाफ 30 जून को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनायें।

## जाति-धर्म के नाम पर बेकसूर लोगों को पीट-पीट कर मार देने की घटनाओं की निन्दा की

**अहमदाबाद (गुजरात) :** यहां जमालपुर, खण्ड नी शेरी स्थित वसन्त राजब के स्मारक पर मूवमेंट फॉर सेक्यूलर डेमोक्रेसी की ओर से 1 जुलाई को 1946 के साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए शहीद हुए वसन्त राजब का 71वां शहीदी दिवस मनाया गया।

मूवमेंट फॉर सेक्यूलर डेमोक्रेसी ने ''नोट इन माई नेम'' आन्दोलन का समर्थन किया और जात-पात और धर्म के नाम पर बेकसूर लोगों को पीट-पीट कर मार देने की घटनाओं की भी निन्दा की।

## साम्प्रदायिकता, जात-पात, वर्णविद्वेष, वंशमूलीय नफरत को भड़का रहा है बेरोजगारी की समस्या के समाधान में नाकाम पूंजीवादी शासक वर्ग

### 70वें पार्टी स्थापना दिवस पर कोलकाता की जनसभा में

### कॉमरेड प्रभास घोष का भाषण

(गतांक से आगे)

**अविभाजित सीपीआई ने यदि मार्क्सवाद को विकसित किया होता तो एसयूसीआई( सी ) की कोई जरूरत ही नहीं होती**

पश्चिम बंगाल की शानदार परम्परा रही है। भारतीय नवजागरण पहले पहल अविभावित बंगाल से शुरू हुआ था। राममोहन-विद्यासागर ने धार्मिक चिंतन के खिलाफ यहीं से संघर्ष शुरू किया था। उसी धारा में आये रवीन्द्रनाथ-शरतचंद्र-नजरूल जैसे अग्रज, देशबंधु चितरंजन दास, बिपिनचंद्र पाल, सुभाषचंद्र बोस, खुदीराम, बाघा जतीन, सूर्यसेन, ज्योतिबा राव फुले, प्रीतिलता और अनेकों उत्कृष्ट चरित्र जो आजादी आंदोलन में शहीद हो गये। बंगाल क्रांतिकारियों का केन्द्र बिन्दु था। इस वजह से नहीं कि बंगालियों में कोई खास विशेषताएं थी बल्कि इस तथ्य की वजह से कि बंगाल में पाश्चात्य शिक्षा पहले लागू की गई थी क्योंकि ब्रिटिश शासित भारत की प्रथम राजधानी कोलकाता थी। 1917 में रूस की प्रथम सफल समाजवादी क्रांति, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों मे समाजवाद की स्थापना और फिर चीन में सफल क्रांति के प्रभाव के साथ ही साथ अविभाजित बंगाल में क्रांति के शानदार रुझान की वजह से 1950 और 1960 के दशकों में पश्चिम बंगाल में वाम जनवादी आंदोलन परवान चढ़ा था। उसने अविभाजित सीपीआई को ताकतवर बनने में मदद की। लेकिन ये खेद का

कोलकाता : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. प्रभास घोष

विषय है कि अविभाजित सीपीआई मार्क्सवाद को कभी अमल में नहीं लायी। यदि उन्होंने मार्क्सवाद को विकसित किया होता तो कठिन व कष्टसाध्य संघर्ष के जरिये भारत की सरजमीन पर सही कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में एसयूसीआई(सी) के निर्माण की जरूरत ही नहीं होती। आजादी आंदोलन के दौरान अविभाजित सीपीआई का इतिहास मार्क्सवाद-विरोधी गतिविधियों की गाथा है। 1925 में विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के कर्णधार महान स्टालिन ने औपनिवेशिक भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करके दिखाया था कि चीन के मुकाबले पूंजीवाद यहां तेज गति के विकसित हो रहा है जो स्थानीय सर्वहाराओं की अनेकों श्रेणियां पैदा कर रहा है, कमोबेश इन्हें ढाल रहा है और क्रांतिकारी आंदोलन के

(शेष पृष्ठ 2 पर)

## जीएसटी का देशभर में विरोध

**पटना( बिहार ) :** 30 जून को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी के तत्वावधान में जीएसटी का सख्त विरोध करते हुए जे. पी. गोलम्बर से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च में शामिल लोग जीएसटी के खिलाफ हाथों में तख्तियां लिये हुए केन्द्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगा रहे थे। प्रतिवाद मार्च भगत सिंह चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया।

सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला सचिव साधना मिश्रा ने कहा कि जीएसटी लागू होने के पहले से ही तमाम आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ बढ़ेगा। नतीजतन दवाओं सहित करीब-करीब रोजमर्रा की सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। कॉ. मिश्रा ने कहा कि तमाम तरह की

(शेष पृष्ठ 8 पर)

## कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 1 का शेष)

उभार के साथ भारत का राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग दो भागों में बंट गया है, एक क्रांतिकारी हिस्सा (पेटी बुर्जुआ) और दूसरा समझौतावादी हिस्सा (बड़ा बुर्जुआ) जो साम्राज्यवाद से भी अधिक क्रांति से डरता है और अपने खुद के देश के हितों से ज्यादा यह अपने मनी बैग के बारे में ज्यादा चिंतित है, मुख्य रूप में बुर्जुआ वर्ग के समझौतापरस्त तबके ने पहले ही साम्राज्यवाद से सांठ-गांठ कर ली है। इन तमाम बातों की व्याख्या करने के बाद भारत में कम्युनिस्टों के कार्यभारों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, ''कम्युनिस्ट पार्टी समझौतापरस्त राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग को अलग-थलग करने के बाद, बुर्जुआ वर्ग की क्रांतिकारी विंग के साथ एक खुला मंच बना सकती है और बनाना चाहिए ताकि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में शहरी और ग्रामीण पेटी बुर्जुआ विशाल जनता को नेतृत्व दिया जा सके।'' (द पोलिटिकल टास्क्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल्स ऑफ द इस्ट, संकलित रचनाएं, खण्ड 7)

इस देश में नेताजी सुभाषचंद्र बोस क्रांतिकारिता के रुझान का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन सीपीआई ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से सुभाषचंद्र को हटाने के षड़यंत्र में सीपीआई ने दक्षिणपंथी गांधीवादी नेतृत्व का साथ दिया। सुभाषचंद्र ने बड़े खेद के साथ कहा, ''त्रिपुरी हमारे लिए स्पष्ट रूप से एक पराजय थी. .. यह मामला था कि बिस्तर पर पड़ा एक बीमार आदमी ओल्ड गार्ड के 12 धुरंधरों से लड़ रहा था...सात प्रान्तीय मंत्री थे...और गांधीजी का नाम प्रभाव और रूतबा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) नेतृत्व के विश्वासघात की वजह से भी हम हारे...कम्युनिस्ट पार्टी भी सीएसपी के साथ तालमेल में थी।'' (क्रोसरोड्स) उसके बाद भी उन्होंने रामगढ़ कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए सीपीआई को बुलाया था ताकि उनके साथ लेफ्ट कन्सोलिडेशन कायम किया जा सके। लेकिन सीपीआई ने उत्तर नहीं दिया। इससे आहत होकर उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म जैसी महान विचारधारा भारत में जड़ें नहीं जमा सकी क्योंकि जिन्हें यहाँ कम्युनिस्ट के रूप में जाना जाता है वे ऐसी नीतियाँ और प्रोग्राम अपना रहे हैं जो एक दोस्त को भी दुश्मन बना देती हैं। एक दोस्त को नजदीक लाने की बजाय उन्होंने उसे दूर धकेल दिया। सुभाषचन्द्र को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के दक्षिणपंथी गांधीवादी नेतृत्व ने उनके खिलाफ षड़यंत्र रचा था। यदि सीपीआई तब उनका समर्थन कर देती तो भारत का इतिहास अलग ही हो सकता था। यदि एक सही कम्युनिस्ट पार्टी ने आजादी आंदोलन में विशेषकर 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन के दौरान अपनी सही भूमिका निभायी होती और सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज (आईएनए) के संघर्ष तथा 1946 में बॉम्बे पोर्ट में उठ खड़े हुए नौसेना के विद्रोह के जोरदार असर का इस्तेमाल किया होता तो पूंजीपति वर्ग कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता था। सैकड़ों शहीदों की कुर्बानियों से आलोकित शानदार स्वतंत्रता संग्राम का इतना दुखद अंजाम नहीं हुआ होता। लेकिन ऐसी एक पार्टी उस समय मौजूद नहीं थी। इसीलिए कॉमरेड शिवदास घोष ने एसयूसीआई (सी) का निर्माण किया।

### क्रांतिकारी विचारधारा का सारतत्व उसके उच्च सांस्कृतिक मान में निहित है

कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया है कि अविभाजित सीपीआई और बाद में सीपीआई(एम) सहित विभिन्न टुकड़ों में बंटे गुटों के नेताओं ने मार्क्सवाद को जीवन-दर्शन के रूप में कभी नहीं अपनाया। राज्यसत्ता के आर्थिक-राजनैतिक चरित्र का निर्धारण करते हुए और मौजूदा सामाजिक-सांस्कृतिक परम्परा का सही-सही निर्धारण करते हुए, इस देश की ठोस परिस्थिति में मार्क्सवाद को वे ठोस रूप से लागू नहीं कर सके और विशेषीकृत नहीं कर सके। इसलिए वे भारतीय परिस्थिति में मार्क्सवाद का ठोस रूप से निर्धारण नहीं कर सके। इसे लेनिन ने रूस में किया था और इसी प्रक्रिया में दिखाया था कि रूस में और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग में मार्क्सवाद की ठोस समझ क्या है। इसे हम लेनिनवाद कहते हैं। माओ त्से-तुंग ने चीन की सरजमीन पर मार्क्सवाद को विशेषीकृत किया जिसे हम माओ त्से-तुंग चिंतन कहते हैं। लेकिन भारत में सीपीआई यह नहीं कर पाई। कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया था कि उन्होंने कभी कम्युनिस्ट संस्कृति को नहीं पनपाया। उन्होंने आगे सिखाया कि कम्युनिज्म न केवल अर्थव्यवस्था में निजी मालिकाने का खात्मा करेगा बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को भी व्यक्तिवाद के चंगुल से मुक्त करेगा। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रह जायेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ एकाकार हो जायेगा क्रांति और समाज के स्वार्थ के साथ। निजी सम्पत्ति का सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से ही उन्मूलन नहीं करना है, बल्कि प्यार-मोहब्बत-खुशी-आवेग-भावनाएं आपसी संबंध में, व्यवहार और आचरण में - हर चीज निजी सम्पत्तिजनित मानसिक जटिलता से मुक्त होनी चाहिए। एक कम्युनिस्ट का उच्चतर सांस्कृतिक स्तर ऐसा होना चाहिए। भारत की सरजमीन पर मार्क्सवाद को विशेषीकृत करने के क्रम में कॉमरेड शिवदास घोष ने यह अवधारणा प्रदान की थी जब क्रांति का स्तर पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति निर्धारित किया गया था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग राजसत्ता पर काबिज हो चुका था। उन्होंने यह भी दिखाया कि भारतीय पूंजीवाद एकाधिकार पूंजी के स्तर पर पहुंच गया है, वित्तीय पूंजी को जन्म दे चुका है और इस प्रकार पूंजीवाद की चरम अवस्था यानी साम्राज्यवाद के स्तर पर पहुंच गया है। अविभाजित सीपीआई ने कभी कम्युनिस्ट संस्कृति को नहीं पनपाया। इस उच्चतर स्तर को हासिल करने का संघर्ष हमारी पार्टी में जीवंत है। हम इसको जीवंत और जोशीला बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो हमारा विरोध करते हैं वे भी स्वीकार करते हैं कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता शिष्ट, सौम्य, सज्जन और सुशील हैं। कैसे हमारे कार्यकर्ता हंसते-हंसते तमाम तकलीफें झेल लेते हैं? इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? प्रेरणा का स्रोत और झरना है कॉमरेड शिवदास घोष का चिंतन। उन्होंने कहा था क्रांतिकारी संस्कृति का सारतत्व चरित्र के उच्चतर मान में निहित है। इसका जीवंत अभ्यास हमारी पार्टी में है। हमारे कार्यकर्ता इसी तरह से तैयार किये जाते हैं। सीपीआई इस रास्ते पर चली ही नहीं। उस समय भी जब 1950 के दशक में सीपीआई आंदोलन के अंदर थी और उनके नेतागण और कार्यकर्ता गिरफ्तारियां और कैद का सामना कर रहे थे उन्होंने कम्युनिस्ट संस्कृति को नहीं पनपाया। उन्होंने कभी भी हिन्दू और मुस्लिम दोनों के साम्प्रदायिक विचारों के खिलाफ सैद्धांतिक संघर्ष नहीं चलाया जो इन दोनों समुदाय के लोगों के बीच प्रचालित थे। जाहिराना तौर पर उन्होंने एक वामपंथी आवरण बनाये रखा। लेकिन वे लोगों को चिंतन के क्षेत्र में मार्क्सवाद पर आधारित सर्वहारा वर्ग दृष्टिकोण प्रदान करने में नाकाम रहे। समाज न तो जातिवादी, धार्मिक, प्रजातीय या प्रांतीय आधार पर बंटा हुआ है, न ही हिन्दुओं या मुसलमानों, बंगालियों या आसामियों के रूप में विभाजित है। यहां दो वर्ग हैं-पूंजीपति और मजदूर, शोषक और शोषित, गरीब और अमीर। उन्होंने इस वर्ग नजरिये के आधार पर लोगों को शिक्षित नहीं किया। इस मूलभूत कमजोरी के साथ वामपंथी आंदोलन जैसे तैसे चल रहा था। फिर पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) सत्तासीन हो गई और पूरी तरह से मार्क्सवाद-विरोधी गैर-वामपंथी नजरिये से सरकार का संचालन शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट क्यों संसदीय चुनावों में हिस्सा लेते हैं? लेनिन ने सिखाया था कि जितनी दूर तक संसदीय चुनाव के बारे में लोगों के अंदर भ्रम बना हुआ है और क्रांति के लिए तैयार नहीं हुये हैं तब तक कम्युनिस्टों को चुनाव में हिस्सा लेने की जरूरत है और यदि चुने गये तो लोगों का मोहभंग करने के लिए संसद में जायेंगे। लेकिन चुनाव में बहुमत हासिल हो जाने और सरकार बनाने का मौका मिलने के मामले में उनकी भूमिका क्या होगी? यह लेनिन द्वारा नहीं बताया गया था क्योंकि उनके समय में ऐसा सवाल सामने नहीं आया था। जवाब दिया मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर कॉमरेड शिवदास घोष ने। उन्होंने बताया कि यदि चुनाव में वामपंथियों-कम्युनिस्टों को बहुमत मिल जाता है और बुर्जुआ सेटअप में सरकार बनाने का मौका आता है तो उस सरकार का दृष्टिकोण और नजरिया जैसे भी हो सत्ता से चिपके रहने का या पूंजीपति वर्ग की स्वार्थ सेवा का नहीं होगा। ऐसी सरकार का उद्देश्य होगा जो भी थोड़ा बहुत समय उनको मिला है उस दौरान वर्ग और जनसंघर्षों को तीव्रतर करना। यदि इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने की वजह से पूंजीवादी राजसत्ता द्वारा उन्हें सत्ता से बाहर भी कर दिया जाये तो यह राजसत्ता का असल चरित्र समझने में लोगों की मदद करेगा और संसदीय डेमोक्रेसी के झांसे के बारे में उनका मोहभंग करेगा।

सीपीआई(एम)-नीत वाम फ्रंट सरकार ने बंगाल में 34 साल राज किया। यह शासन किसी भी मायने में कांग्रेस, बीजेपी या टीएमसी से भिन्न नहीं था। 1950 से 1966 के दौरान जो कुछ थोड़ा बहुत संघर्षशील मन सीपीआई(एम) और सीपीआई का था वह उनके द्वारा सत्ता का स्वाद चखने के बाद तेजी से खत्म होना शुरू हो गया और उनका समझौतापरस्त सोशल डेमोक्रेटिक चेहरा बेनकाब होना शुरू हो गया। धीरे-धीरे उन्होंने खुद को शासक पूंजीपति वर्ग के सेवादारों में तब्दील कर लिया।

### सीपीआई(एम)-नीत फ्रंट के लम्बे अर्से के शासन ने किया वामपंथ को बदनाम

उनके लम्बे अर्से के जनविरोधी पूरे शासन के दौरान, सिर्फ हमारी ही पार्टी थी जिसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद के महान झण्डे को बुलंद रखते हुये निरंतर संघर्ष संचालित किया था। सीपीआई (एम)-नीत सरकार के खिलाफ आंदोलन संचालित करने के दौरान हमारी पार्टी के131 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहादत को गले लगाया। आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल स्तर पर अंग्रेजी की पढ़ाई को वापस लाने के लिए हमने लम्बे वर्षों तक आंदोलन जारी रखा था। आंदोलनों को संचालित करने के जरिये हमने बहुत सी मांगे हासिल भी की हैं। यदि सीपीआई(एम) ने 34 साल लम्बा अपना शासन मजदूर वर्ग के नजरिये से चलाया होता तो वामपंथ मजबूत हुआ होता और इसका असर पूरे देश में महसूस किया गया होता। वर्ग संघर्ष तेज हो गया होता। इसकी बजाये उन्होंने अपने वामपंथी आवरण में बुर्जुआ वर्ग दृष्टिकोण के जरिये भारी नुकसान पहुंचाया है, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की संघर्ष की भावनाओं को तबाह किया है और उन्हें अवसरवाद के गर्त में डुबो दिया है। सत्ता के बाहर कर दिए जाने के तुंरत बाद सीपीआई(एम) की हालत देखें। अगर वे सत्ता में नहीं हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में फील्ड एक्टीविटी करने का साहस नहीं रहता है। आज वे सत्ता में नहीं हैं इसलिए शक्तिहीन हो गये हैं। उनके आह्वान पर कोई नहीं आता है। न्यूनतम साहस भी उनके कार्यकर्ताओं में नहीं रहा है। जब वे सत्ता में थे, किसी अन्य बुर्जुआ पार्टी की तरह ही उन्होंने देशी और विदेशी पूंजी की सेवा की थी, पुलिस-प्रशासन और गुण्डों की

(शेष पृष्ठ 4 पर)

# आंगनवाड़ी कर्मियों को बधुंआ बनाने वाले फरमान का विरोध

**रोहतक (हरियाणा) :** एआईयूटीयूसी के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. सत्यवान और प्रदेश सचिव कॉ. हरिप्रकाश ने 24 जून को जारी एक बयान में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बंधुआ बनाने वाले ताजा काले फरमान का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र-विरोधी, मनमाना व असंवैधानिक करार देते हुए प्रदेश सरकार से इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने, इसे जारी करने के दोषी निदेशक, महिला व बाल विकास विभाग हरियाणा को पद से हटाने की मांग की है। उक्त अधिकारी ने प्रदेश भर की सभी जिला स्तरीय कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र क्रमांक 10296-316 सीडी-11/डब्ल्यू सीडी/2017 दिनांक 14 जून 2017 भेज कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के धरने-प्रदशनों या हड़ताल पर रोक लगाई है। यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसकी सेवाएं समाप्त करने की धमकी इस काले फरमान में दी गई है।

केन्द्रीय श्रमिक संगठन का मानना है कि देश का संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता जिनमें अपनी बात कहने की आजादी है। निदेशक का यह फरमान संविधान की धारा 19 और 13 की सरेआम धज्जियां उड़ाता है। इसलिए पूरी तरह से गैर कानूनी व मनमाना है। श्रमिक नेताओं ने कहा कि यह काला फरमान राजाओं के क्रूर शासन की कड़वी याद दिलाता है जब प्रजा की जबान पर ताला लगाकर रखा जाता था और बात-बिन-बात उसे कोल्हू में पीड़ा जाता था।

उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रही हैं जो कि कोई गुनाह नहीं है। उन्हें भी बेहतर जीवन जीने का हक है, वे देश की दुश्मन नहीं हैं जो उन पर ऐसा क्रूर शिकंजा कसा जा रहा है।

सर्वविदित है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मामूली सा मेहनताना मिलता है। एक-एक साल तक आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया नहीं दिया जाता है। रजिस्टर व कागजात तक उन्हें अपनी जेब से खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। लाभार्थी महिलाओं व बच्चों का पोषाहार घटिया दर्जे का व तोल में कम दिया जाता है। सरकार का व्यवहार इनसे दोगला है। सजे-सजाये मंचों से इनकी तारीफ की जाती है लेकिन निदेशक से लेकर ब्लॉक अधिकारी तक इनसे बंधुआ से भी बुरा बर्ताव करता है। आये दिन इनसे गैर-आंगनवाड़ी कार्य करवाये जाते हैं। सरकार की इन सब गलत नीतियों व गलत कार्यप्रणाली का ठिकरा भी इन्हीं के सिर पर फोड़ा जाता है। इस शोषण-दमन भरे माहौल के खिलाफ ये अपना मुंह न खोल सकें, इसके लिए जब मर्जी आये इन्हें नौकरी से हटाने का निरंकुश अधिकार राजाओं की तरह अधिकारी अपने हाथ में रखते हैं। इस ताजा काले फरमान से भीषण दमन चक्र को लागू किया जा रहा है। श्रमिक नेताओं ने मजदूर-कर्मचारी व हरियाणा का मेहनतकश अवाम से इस फरमान का पुरजोर विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दूसरी ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ हर सम्भव संघर्ष किया जायेगा।

# राजस्थान में मनाया गया एआईडीवाईओ स्थापना दिवस

**जयपुर :** 26 जून को एआईडीवाईओ के 51वें स्थापना दिवस पर यहां लुणियावास क्षेत्र के पालड़ी मीणा जेडीए कॉलोनी, ई-ब्लॉक पार्क में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसकी तैयारी के दौरान आरएसएस के सदस्यों द्वारा बाधा डालने का प्रयास किया गया, मगर इलाके के नौजवानों के सक्रिय विरोध के कारण वे ऐसा करने में सफल नहीं हो सके।

सभा की शुरूआत में एआईडीवाईओ के साथियों ने कई क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किये। राजस्थान राज्य सांगठनिक कमेटी के प्रभारी कॉ. कुलदीप सिंह ने स्थापना दिवस मनाने का महत्व बताया और संगठन को मजबूत करने के लिए नौजवानों से अपील की। राज्य कार्यालय सचिव कॉ. सुनील कुमार ने अपने वक्तव्य में संगठन द्वारा राज्य में बेरोजगारी, नशाखोरी, अपसंस्कृति और महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ चलाये जा रहे आन्दोलन के बारे में बताया। एआईडीवाईओ के दिल्ली राज्य सचिव व केन्द्रीय काऊन्सिल सदस्य कॉ. अमरजीत कुमार ने मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया।

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी समस्याओं का हल पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति में निहित है। यह साल महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष है, जब रूस के मजदूर-किसानों ने पूंजीवाद को उखाड़ फेंका था और चंद वर्षों में ही बेरोजगारी, नशाखोरी, वेश्यावृत्ति, महिलाओं पर होने वाले अपराध जैसे अभिशापों से मुक्त कर समाज में उच्च सांस्कृतिक स्तर कायम करने में सफल हुए थे। उन्होंने सभी नौजवानों से संगठन को मजबूत करने और इस आन्दोलन में जुड़ने की अपील की।

सभा की अध्यक्षता राज्य कमेटी सदस्य धीरूसिंह ने की।

# महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष पर जनसभा शहर में निकाला शानदार जुलूस

**भिवानी (हरियाणा) :** महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 29 जून को यहां स्थानीय राजपूत धर्मशाला में जनसभा आयोजित की गई और शानदार जुलूस निकाला गया। इसका आयोजन एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की पहल पर गठित महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष समारोह आयोजन कमेटी, भिवानी की ओर से किया गया। जनसभा को मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रामफल ने की।

वक्ताओं ने कहा कि इस साल दुनिया भर में कमेरा वर्ग महान लेनिन के नेतृत्व में हुई महान नवम्बर क्रान्ति का शताब्दी वर्ष मना रहा है जिस क्रान्ति ने रूस में पूंजीवादी शोषण की जंजीरों को तोड़ डाला था और धरती पर शोषणमुक्त पहला समाजवादी राज्य कायम किया था। उन्होंने कहा कि मेहनतकशों की इस क्रान्ति का शताब्दी वर्ष शानदार ढंग से मनाना, इसकी सीखों को जन-जन तक ले जाना और वर्तमान राष्ट्रीय-अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में इसके महत्व को समझना हम सब के लिए निहायत जरूरी है।

वक्ताओं ने कहा कि साम्राज्यवादी-पूँजीवादी शासन-शोषण के खिलाफ देश-दुनिया के मेहनतककशों का रोष फूट पड़ रहा है। वे आवाज उठा रहे हैं–पूँजीवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, समाजवाद जिन्दाबाद। इन जुझारू लोगों को एक दिन वैज्ञानिक समाजवाद का ज्ञान होगा ही। महान नवम्बर क्रान्ति की शिक्षा के आधार पर वे देश-देश में मुक्ति-संघर्ष गठित कर साम्राज्यवाद-पूँजीवाद के किले को चकनाचूर कर देंगे। फिर दुनिया

भिवानी : नवम्बर क्रांति शताब्दी वर्ष पर हुई सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट

भर में कायम होगा समाजवाद। इसी रास्ते पर चलते हुए मानव जाति को हर तरह के शोषण-उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। जरूरत के क्षेत्र से आजादी के क्षेत्र में पदार्पण होगा। वर्गहीन समाज कायम होगा। सामाजिक विकास के नियम की यही है अवश्यम्भावी परिणति।

सभा का संचालन पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कॉ. धर्मवीर सिंह ने किया। पार्टी के जिला कमेटी सदस्यों कॉमरेड्स राजकुमार जांगड़ा, रोहतास सैनी, सुखबीर, राजकुमार बासिया व जिले सिंह ने भी सभा को सम्बोधित किया। सभास्थल पर फोटो व उद्धरण प्रदर्शनी भी लगाई गई। सभा के बाद शहर में एक सुसज्जित और अनुशासित विशाल जुलूस निकाला गया।

## कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 2 का शेष)

मदद से विरोध की आवाज का गला घोंटा था, दहशत फैलाई थी, धमकियां दी थी और भ्रष्टाचार और विभिन्न तरह की अनैतिक-निर्लज्ज-दुराचारी गतिविधियों में लिप्त रहे थे। उन्होंने अपनी संख्या किसी विचारधारा या सिद्धांत के दम पर नहीं बढ़ाई थी बल्कि सुविधाएं मुहैया कराने के बल पर बढ़ाई थी जैसे लाइसेंस और परमिट देना और कॉंट्रेक्टरों तथा प्रोमोटरों के साथ सांठगांठ करना। इस तरह से उन्होंने पुलिस-प्रशासन पर, शिक्षा संस्थानों पर लगभग सभी जगहों पर पार्टी आधिपत्य थोप दिया था। इस प्रकार उन्होंने वामपंथ को बदनाम किया, मार्क्सवाद की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बहुत अर्सा पहले 1969 में ही कॉमेरड शिवदास घोष ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे वामपंथ को कलंकित कर रहे हैं और दक्षिणपंथी जनसंघ (मौजूदा बीजेपी का पूर्ववर्ती) इसका फायदा उठाएगा। गहरी चिंता के साथ उन्होंने कहा था, '' इस परिस्थिति में विभाजनकारी गुटों और जनसंघ जैसे धार्मिक कट्टरपंथी मौके की ताक में बैठे हैं। वामपंथी आंदोलन के प्रति लोगों के अंदर जो भी थोड़ा बहुत आकर्षण बचा हुआ है ज्यों ही वह खत्म होगा, वे खुलकर सामने आ जाएंगे। शासक सीपीएम के नेतागण इस खतरे के बारे में सचेत नहीं हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा और इसके सारतत्व को धूल में मिलाकर वे बड़ी-बड़ी बातों और मीठी बोली से लोगों को गुमराह कर रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस ने किया था। इस तरह वे कम्युनिज्म की साख को गिरा रहे हैं और इसे बदनाम कर रहे हैं।'' (सम आस्पेक्ट्स ऑफ यूनाइटिड फ्रंट पोलिटिक्स एण्ड पार्टी वर्क, संकलित रचनाएं खण्ड 3, पृष्ठ 155) दूसरे उन्होंने कभी भी लोगों के अंदर साम्प्रदायिकता विरोधी मानसिकता विकसित करने का प्रयास नहीं किया न ही वे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के अंदर मार्क्सवादी विचारधारा का कोई प्रभाव पैदा कर पाये। जो उनके लिए वोट दिया करते थे वे भी परोक्ष रूप से अपने अंदर हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही साम्प्रदायिक विचारों का पोषण करते थे। इसी तरह की तमाम मानसिकताओं के साथ उन्होंने सीपीआई(एम) या अविभाजित सीपीआई का समर्थन किया था। उनका नेतृत्व कभी भी इस बारे में सतर्क नहीं था। सीपीआई (एम) और सीपीआई दोनों ही अब इसकी कीमत चुका रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और समर्थक साम्प्रदायिक ताकतों में शामिल हो रहे हैं। वामपंथी आंदोलन भी कमजोर हो रहा है।

### टीएमसी भी कर रही है वोट बैंक की राजनीति

दूसरी तरफ टीएमसी भी वही वोट बैंक की राजनीति कर रही है। टीएमसी नेतृत्व जानता है कि अच्छा खासा हिन्दू वोट भी हर हालत में उनके पास आएगा। जैसे भी हो वे इस वोट को हासिल कर ही लेंगे चाहे पैसे से खरीद कर या मुफ्त उपहारों की भरमार के माध्यम से जैसे युवाश्री, कन्याश्री, साइकिलों के बांटने और कल्बों को चंदा इत्यादि देकर। उनकी जरूरत है एक मुस्लिम वोट बैंक तैयार करने की। इसको दिखा कर आरएसएस-बीजेपी प्रचार कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, टीएमसी सरकार मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। मैं पूछता हूं टीएमसी शासन के दौरान कितने मुसलमानों को रोजगार मिला है? कितने मुसलमानों की पहुंच शिक्षा तक हुई है? बेरोजगारी की दर हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों में समान है। किसी भी समुदाय को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा है। लोगों को समझना होगा कि यह सब जहरीला झूठा प्रचार है। सच्चाई यह है कि समाज दो वर्गों बंटा हुआ है, पूंजीपतियों वर्ग और मजदूर वर्ग, शोषक और शोषित। हिन्दुओं या मुसलमानों के लिए अलग से कोई रोजगार आवंटित नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तुओं के दाम हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग नहीं हैं। रेल और बस के किराये हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के लिए समान हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क भी किसी भी समुदाय के लिए भिन्न नहीं हैं। जीवन की समस्याएं दोनों के लिए समान हैं। उनमें सभी शोषित उत्पीड़ित हैं। इसी वजह से हम उत्पीड़ित लोगों की एकता चाहते हैं। हमारी पार्टी इसी एकता का निर्माण करने की चाह रखती है।

### एसयूसीआई (सी) हमेशा रही है एकता की पक्षधर, सीपीआई(एम) ने ही इसे तोड़ा

हम पश्चिम बंगाल में वामपंथी एकता चाहते हैं सीपीआई(एम) ने ही 1974 में जयप्रकाश नारायण (जेपी) आंदोलन के दौरान उसे तोड़ा था। उस समय आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ था। हम उस आंदोलन में थे। हमने सीपीआई(एम) और सीपीआई दोनों से उस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया था जो जीवन की ज्वलंत समस्याओं जैसे रोटी-कपड़ा-मकान के लिये था। सीपीआई(एम)-सीपीआई यह बहाना बनाकर आंदोलन से दूर रही कि इसमें आरएसएस-जनसंघ शामिल है। लेकिन बाद में उन्होंने निरंकुशता से लड़ने के नाम पर दो बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। और क्योंकि सीपीआई(एम)-सीपीआई जेपी आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी इसलिए आरएसएस जनसंघ ने इसके सारे लाभ बटोर लिये और अपनी ताकत बढ़ा ली। आरएसएस ने भारत के आजादी आंदोलन का विरोध किया था। क्या आप आरएसएस-जनसंघ का इतिहास जानते हैं? बीजेपी नेताओं से पूछिये जो खुद को अब 'देशभक्तों' के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और विरोधी ताकतों पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगा रहे हैं, आजादी आंदोलन के समय में उनकी 'देशभक्ति' कहाँ गई थी? असल में आरएसएस के सिद्धांतकार एम.एस. गोलवलकर ने खुल्लम खुल्ला आजादी आंदोलन का विरोध किया था। गोलवलकर ने कहा था, ''क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और साझे खतरे का सिद्धांत जो आधार बना है हमारी राष्ट्र की अवधारणा का, इसने हमारे असल हिन्दू राष्ट्रवाद के सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार के मूलतत्व से हमें वंचित कर दिया है और 'आजादी आंदोलनों' को वस्तुतः ब्रिटिश-विरोधी आंदोलनों' मे तब्दील कर दिया है। अंग्रेज-विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद के समतुल्य बना दिया है। इस प्रतिक्रियावादी विचार का हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम पर, इसके नेताओं और आम जनता पर विनाशकारी प्रभाव हुआ है।'' (हम या हमारा राष्ट्रवाद परिभाषित) देखिये कितना खतरनाक विचार है यह! गोलवलकर के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकता की अवधारणा पर आधारित और भारत के तत्कालीन भूखण्ड को केन्द्र करके राष्ट्रवाद का जो आह्वान देशबंधु, चितरंजनदास, लाला लाजपतराय, तिलक, नेताजी सुभाष बोस, भगतसिंह और अन्यों ने दिया था वह प्रतिक्रियावादी था। यही वजह थी कि आरएसएस ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस से पूछिये उन्होंने आजादी आंदोलन में हिस्सा क्यों नहीं लिया था? जब खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा गले लगाया, सूर्यसेन चटगांव में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ रहे थे, बाघा जतीन ब्रिटिश सिपाहियों से टक्कर ले रहे थे और पूरा देश 1942 में 'भारत छोड़ो' आंदोलन के पीछे लामबंद हो गया था, आरएसएस क्यों इन तमाम आंदोलनों से दूर रहा? आरएसएस का स्टैण्ड था कि जब तक आंदोलन हिन्दू राष्ट्रवाद के लिए नहीं होंगे वे इनमें शामिल नहीं होंगे। आरएसएस के अनुसार नेताजी सुभाष बोस, देशबंधु चितरंजन दास, खुदीराम बोस, भगतसिंह, अश्फाक उल्ला और ऐसे ही अन्य स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त नहीं थे। क्या भारत के और पश्चिम बंगाल के नौजवान आज आरएसएस-बीजेपी के सामने नतमस्तक होंगे? क्या ये ताकतें पैसे के प्रलोभन और हिन्दुत्व के नारे से नौजवानों को खरीद लेंगी?

### सुभाषचंद्र बोस ने किया था धर्म और राजनीति को मिलाने का घोर विरोध

सुभाषचंद्र बोस ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था, '' निहित स्वार्थों से प्रेरित लोगों का एक तबका अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दोनों समुदायों के बीच बदअमनी फैला रहा है। ऐसे लोगों को आजादी आंदोलन का दुश्मन मानना चाहिए।'' (सुभाषचंद्र क्लैक्टिड वर्क्स, वोल्यूम 2) फारवड ब्लॉक की बाम्बे कांफ्रेस में उन्होंने कहा था, ''धर्म को पूरी तरह राजनीति से अलग रखना चाहिये...राजनीति को धर्म या अन्य अतिप्राकृतिक अवधारणा से संचालित नहीं होना चाहिए। राजनीति को आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक तर्कशीलता से संचालित होना चाहिए।'' (क्लैक्टिड वर्क्स, वोल्यूम 5) हिन्दुत्व के पैरोकारों की निंदा करते हुए 1940 में झाड़ग्राम की एक मीटिंग में उन्होंने कहा था, ''हिन्दू महासभा के नाम से प्रतिक्रियावादी तत्व जो राजनीति में प्रवेश कर गये हैं वे राजनीति को गंदा कर रहे हैं...हिन्दू महासभा ने भिक्षुओं और सन्यासिनों को हाथ में त्रिशूल लेकर वोट मांगने के लिए भेजा है। प्रत्येक हिन्दू भगवा वस्त्र और त्रिशूल के सामने नतमस्तक होता है। हिन्दू महासभा धर्म का फायदा उठाते हुए और उसे नापाक करते हुए रंगमंच पर प्रकट हुई है...इन देशद्रोहियों को राष्ट्रीय जीवन से अलग-अलग करो। उनकी मत सुनो। हम चाहते हैं कि देश के सभी आदमी और औरतें एकजुट होकर और पूरी लगन के साथ देश की सेवा करें। (आनंद बाजार पत्रिका, 14.5.1940) यदि आज नेताजी सुभाष जिंदा होते तो आरएसएस-बीजेपी की राजनीति के बारे में वे क्या कहते? कैसे देश से साम्प्रदायिकता का खात्मा हो सकता है इसको इंगित करते हुए उन्होंने कहा था, ''मौजूदा परिस्थितियों में साम्प्रदायिकता के कैंसर को नष्ट करना और हमारे जन जीवन में चौतरफा राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करना लगभग असंभव लगता है। लेकिन कितना आसान हो जायेगा यह काम जब एक बार राष्ट्रव्यापी पैमाने पर क्रांतिकारी मानसिकता को विकसित किया जा सकेगा।''(क्रोसरोड्स)

पहले शाहनवाज खान और बाद में रशिद अली आजाद हिन्द फौज (आईएनए) के जनरल थे जो सुभाष चंद्र बोस ने बनायी थी। जब ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि वह कर्नल रशिद अली को फांसी देगी तो सारे देश में उथल-पुथल मच गई थी। हिन्दू और मुसलमान दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। यह बहुत ही दुखदायक है कि आरएसएस-बीजेपी आज ऐसे एक भारत में अपनी पैठ बना रहे हैं। इसी में खतरा अंतर्निहित है।

मैंने पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के चौतरफा संकट को केन्द्रित करके अपनी बात शुरू की थी। पूंजीवाद जिसने अपने उदयकाल में धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद और डेमोक्रेसी के झण्डे को बुलंद किया था, जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ा था, अब यूरोप और अमेरिका के देशों सहित तमाम देशों में नस्लवाद और साम्प्रदायिकता की आग भड़का रहा है। भारत भी कोई अपवाद नहीं है। एकमात्र उद्देश्य है संकटग्रस्त पूंजीवाद को बचाना, उत्पीड़ित लोगों को भ्रमित करना और भटकाव में डालना। पूंजीवाद ने एक दूसरा खतरनाक हमला शुरू किया है। तार्किक मन और इन्सानी गुणों को तबाह करने और चेतना का हनन करने के लिए इसने एक अनिष्टकारी षड़यंत्र रचा है ताकि इन्सानों को अमानवीय प्राणी में तब्दील किया जा सके। यही वजह है कि पूंजीवादी शासक लोगों को शराबखोरी, नशाखोरी और विभिन्न तरह की जुएबाजी में लिप्त करने, पतित संस्कृति में डुबो

(शेष पृष्ठ 6 पर)

# मिड-डे मील कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा

भिवानी : शहर में प्रदर्शन करती हुई मिड-डै मील कार्यकर्ता

बहादुरगढ़ में प्रदर्शन करती हुई मिड-डै मील कार्यकर्ता

**भिवानी (हरियाणा) :** 22 जून को एआईयूटीयूसी से सम्बन्धित मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन के बैनर तले मिड-डे मील कर्मियों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर यहां शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त, भिवानी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मिड-डे-मील कार्यकर्ता श्री चेतराम प्रजापति धर्मशाला में इकट्ठी हुई और सराय चौपटा, घण्टाघर, हांसी गेट होते हुए लघु सचिवालय पहुंची। वहां गेट पर पुलिस द्वारा रोक दिये जाने पर उन्होंने जोरशोर से नारे लगाये।

ज्ञापन में स्कूल के अन्य कर्मचारियों की तरह मिड-डे मील कर्मियों को भी गर्मियों की तथा अन्य छुट्टियों के दौरान का मेहनताना देने, छुट्टियों के पैसे न काटने, मिड-डे मील कर्मियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने, पहले से लगी हुई किसी भी मिड-डे-मील कार्यकर्ता को काम से न हटाने, पुराना नियम बदल कर 15 छात्रों पर एक मिड-डे-मील कार्यकर्ता लगाने, अगर गांव में दो स्कूल हैं तो उनमें से किसी में उन्हें समायोजित करने, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 18000 रुपये न्यूनतम वेतन देने, तब तक घोषित न्यूनतम वेतन जितना मासिक मेहनताना तो कम से कम नियमित रूप से निर्धारित तिथि पर देने, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने, साल में कम से कम दो वर्दियां देने, जरूरी काम होने पर या बीमार पड़ने पर सवेतन अवकाश अन्य कर्मचारियों के समान देने और मिड-डे मील कार्यकताओं के गम्भीर रूप से बीमार पड़ने या दुर्घटना में घायल होने पर मुफ्त इलाज व आर्थिक सहायता और मौत होने पर मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने, छात्रों को गुणवत्ता वाला पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन देने, हर जगह रसोईघर, भण्डारण गैस सिलेण्डरों व चूल्हे आदि जरूरी सामान व बुनियादी सुविधाओं की समय पर समुचित व्यवस्था करने और सुरक्षा के पुख्ता प्रबन्ध करने, मिड-डे मील काम को देखने व प्रबन्ध करने के लिए अलग से स्टाफ भर्ती करने, सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं व पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर करने, पहली से आठवीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली चालू करने की मांग की गई।

यूनियन की जिला प्रधान मीरा देवराला ने कहा कि स्कूल के अन्य कर्मचारियों को साल में 12 महीने का वेतन मिलता है लेकिन कुक-कम-हेल्परों को 10 महीने का। यह भेदभाव है। श्रमिक की बजाय कार्यकर्ता और वेतन की जगह मानदेय की आड़ में इस योजना में कार्यरत श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। सरकार बेरोजगारी का नाजायज फायदा उठा रही है। हाजिरी रजिस्टर, जीवन बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, वर्दी, सवेतन अवकाश, बीमार पड़ने पर इलाज आदि सामाजिक सुरक्षा उपायों, हितलाभों व सुविधाओं से भी मिड-डे मील कार्यकर्ता वंचित हैं। स्कूल में एक भी बच्चा कम होने पर मिड-डे मील कार्यकर्ता को काम से हटा दिया जाता है चाहे वह कितने ही साल से काम करती हो। हमारी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक बेरोक पास करने की नीति से शिक्षा चौपट हो जाने से छात्र सरकारी स्कूलों से पलायन कर रहे हैं। इसका कारण दूर करने की बजाय हमें नौकरी से हटाया जा रहा है। यह सरासर अन्याय है। उन्होंने मांग की कि कई सालों से पुरानी लगी हुई मिड-डे मील कार्यकर्ता को हटाना नहीं चाहिए।

मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन की जिला उप प्रधान राजबाला पालुवास ने बताया कि मिड-डे मील स्कीम में बेहद गरीब, बेसहारा और विधवा महिलाएं लगी हुई हैं जो परिवार की आमदनी का एकमात्र सहारा हैं। छात्रों के लिए खाना बनाने वाली महिलाएं स्कूल खुलते ही काम पर आती हैं और स्कूल की छुट्टी होने पर घर जाती हैं। वे रोजाना लगभग 8 घण्टे काम करती हैं। मिड-डे मील बनाने के बाद उनको कोई दूसरा काम करने का भी समय नहीं बचता है। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी मिड-डे मील कुक को मामूली सा 2500 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। गर्मियों व अन्य छुट्टियों का तो यह मेहनताना भी नहीं दिया जाता है। इतने थोड़े से पैसों से परिवार का गुजारा नहीं होता है।

प्रदर्शनकारियों को एआईयूटीयूसी के जिला कमेटी सदस्य राजकुमार बासिया, जिला सचिव धर्मवीर सिंह व जिला प्रधान रामफल ने भी सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि सरकारी स्कीम के तहत मिड-डे मील कार्यकर्ता अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में प्रदान कर रही हैं। मिड-डे मील कार्यकर्ता काम जब सरकारी करती हैं तो सरकार को अपना श्रमिक-कर्मचारी भी मानना चाहिए। मिड-डे मील कार्यकर्ताओं सहित सभी स्कीम वर्करों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, जीने लायक वेतन देना, भारतीय श्रम सम्मेलन व अन्तर्राष्ट्रीय लेबर कन्वेन्शनों की पालना करना और कमेटियों की सिफारिशों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज कमरतोड़ महंगाई में देना तो चाहिए 18000 रुपये मासिक वेतन लेकिन हमें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन जितना मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार की नजर में मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं के लिए क्या महंगाई बढ़ती ही नहीं है? वरना क्या कारण है कि मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं को महंगाई भत्ता या महंगाई के हिसाब से मेहनताना नहीं दिया जाता है? वेतन में वार्षिक बढ़ोतरी क्यों नहीं होती है? सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से कम पैसों में मिड-डे मील कुक-कम-हेल्परों से काम कराना भी बंधुआ मजदूरी कराने के बराबर है और शोषण है। उन्होंने मिड-डे मील कार्यकर्ताओं की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का सरकार से अनुरोध किया। वक्ताओं ने मिड-डे मील कर्मियों से सभी ज्वलंत मांगों को लेकर आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया।

प्रदर्शन में सुदेश दुल्हेड़ी, बिमला पैंतावास, संतोष तिगड़ाना, राजवंती धिराणा, सरीता उमरावत, सुदेश व कृष्णा गुजरानी, गुड्डी कोहाड़, ज्योति सांगा, चमेली बड़ेसरा, सुनीता व लाली बड़ाला, मीना धनाना, कृष्णा नाथुवास, विद्या इन्दीवाली आदि भी शामिल थी।

# एआईडीवाईओ का ब्लॉक सम्मेलन सम्पन्न

**ढकवा प्रतापगढ़ (उ.प्र.) :** 29 जून को यहां डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शिक्षण संस्थान में एआईडीवाईओ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आसपुर देवसरा ब्लॉक सम्मेलन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत संगठन का झण्डारोहण और शहीद वेदी पर पुष्पार्पण से हुई। तत्पश्चात सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गान गाया गया। कॉ. मुन्ना और कॉ. दिनेश कांत मौर्य ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किया। कॉ. अच्छेलाल गौतम, कॉ. जयप्रकाश, कॉ. विजयानंद, श्री हरिशंकर यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष कॉ. कमलेश मौर्य ने स्थापना दिवस मनाने की प्रासंगिकता बतायी। जिला इंचार्ज कॉ. रामकुमार यादव ने सांगठनिक रिपोर्ट और प्रस्तावित ब्लॉक कमेटी गठन का प्रस्ताव पेश किया। इनका सभी ने सर्व सम्मति से समर्थन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉ. यशवंत राव ने की और संचालन कॉ. उमाशंकर यादव ने किया। नवनिर्वाचित ब्लॉक कमेटी में कॉ. उमाशंकर यादव को अध्यक्ष, श्री अच्छेलाल गौतम को सचिव चुना गया।

# धरने-प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाने का आंगनवाड़ी कर्मियों ने किया विरोध

**रेवाड़ी (हरियाणा) :** आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बिना नोटिस दिये नौकरी से हटाने, 1482 कार्यकर्ताओं की सर्विस खत्म करने का नोटिस दिये जाने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं द्वारा धरना-प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाये जाने, प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर उन्हें नौकरी से हटाने के सरकारी तुगलकी फरमान के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन के बैनर तले सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्करों व हैल्परों ने यूनियन की जिला सचिव कृष्णा यादव के नेतृत्व में 23 जून को जोरदार जुलूस निकाला और सरकार के इस तुगलकी फरमान की प्रतियां जलाई। उन्होंने इस आशय का एक ज्ञापन सरकार को भेजा। इससे पहले सभी कार्यकर्ता शहर के राव तुलाराम पार्क में एकत्रित हुई। इस अवसर पर यूनियन के सलाहकार कॉमरेड राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि बिना सुनवाई के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से हटाना और धरना-प्रदर्शन में शामिल होने वाली कर्मियों को हटाने का फैसला असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, श्रम अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला जायज हकों के लिए उठी आवाज का गला घोंटने वाला है।

सरकार की इस दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ जोरदार आन्दोलन खड़ा करना ही एकमात्र विकल्प है।

प्रदर्शनकारियों को एआईयूटीयूसी के जिला प्रधान अमृतलाल, सचिव बलराम एवं संयुक्त कर्मचारी मंच के नेता हरिसिंह मुलौधिया और जेपीए के नेता शेर सिंह ने सम्बोधित किया।

# पहली कक्षा से पास-फेल प्रणाली पुनः लागू करवाने मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

**गुड़गांव :** कक्षा पहली से आठवीं तक पास-फेल प्रणाली पुनः लागू करवाने तथा पांचवीं व आठवीं में बोर्ड परीक्षा लागू करवाने, 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम का निःशुल्क पुनर्मूल्यांकन करवाने, स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षक भर्ती करवाने की मांगों को लेकर आल इंडिया डीवाईओ, जिला कमेटी की ओर से 7 जून को प्रदर्शन करके डी सी गुड़गांव के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

धरने-प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रदेश संयोजक बलवान सिंह ने किया।

डीवाईओ नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इसी सत्र से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली तथा 5वीं व 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू नहीं की, तो छात्र-नौजवानों को मजबूरन सड़कों पर निकलना पड़ेगा और सरकार को उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा।

प्रदर्शन में सुनील कुमार, वजीर सिंह, महेन्द्र सिंह, रामकुमार आदि ने हिस्सा लिया।

## कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 4 का शेष)

देने पर उतारू हैं। एक तरफ गोवध बंद करने का नारा उठाया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ शराब की दुकानें जगह-जगह तेजी से खोली जा रही हैं। दोनों काम साथ-साथ किये जा रहे हैं। जितनी अधिक संख्या में शराब की दुकानें, उतने ही अधिक बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। कोई बलात्कारी के रूप में पैदा नहीं होता है। सभी शिशु मानव देह और मानव मस्तिष्क के साथ पैदा होते हैं। फिर, ये बलात्कारी कहां से आ रहे हैं? कौन इन्सानों को अमानवीय बलात्कारियों के रूप में तब्दील कर रहा है? यह जराग्रस्त समाज है जो बलात्कारियों को जन्म दे रहा है। रवीन्द्रनाथ, शरतचंद्र, नजरूल, प्रेमचंद, ज्योतिबाराव फुले या सुब्रमण्यम भारती ने बलात्कारों, सामूहिक बलात्कारों, जनसंहारों और व्यभिचार की इतनी भयावह प्रचण्डता को नहीं देखा होगा, न ही सुभाषचंद्र, भगतसिंह या खुदीराम ने देखा होगा। ऐसी घटनाएं हर रोज, हर घंटे घटित हो रही हैं। ये पूंजीवाद है जो इन तमाम बुराइयों को पनपा रहा है। यहां तक कि पशुओं में भी बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसी कोई बात नहीं होती है। ये बलात्कारी एक नये किस्म के जीव हैं-शरीर आदमी का लेकिन मानवीय संवेदनाओं से महरूम-जिन्हें पूंजीवाद ने यूरोप, अमेरिका और भारत में पैदा किया है। शासक पूंजीवाद और इसके सेवादार फिल्मों, टी.वी., मोबाइल फोनों और अन्य ऐसे तमाम माध्यमों के जरिये सड़ी-गली, घृणित यौन-विकृति को फैलाने में लिप्त हैं ताकि इंसानों खासकर युवाओं की नैतिकता और उनके मानवीय गुणों का हनन करते हुए उन्हें यौन दासता का शिकार बनाया जा सके। क्योंकि यदि मानवीय गुणों, संवेदना या तार्किकता को तबाह नहीं किया गया तो सवाल उठेंगे, बहस होंगी और प्रतिवाद होंगे। इसी वजह से यह आक्रमण इतना खतरनाक है। इस हमले का सामना हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कर रहे हैं।

### समाजवादी खेमें के न रहने से बेलगाम हो गया है विश्व पूंजीवाद-साम्राज्यवाद

इन हालात में, इस शातिर हमले को रोकने के लिए जो जरूरी है, वह है कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिंतन के आधार पर उत्पीड़ित जनता की व्यापक एकता कायम की जाये। मजदूर-किसानों और मध्यम वर्ग के आंदोलनों के बढ़ते उफान की जरूरत है। उत्पीड़ित लोगों के तमाम तबकों को ऐसे आंदोलन के भंवर में खींच लाने की जरूरत है। यह सच है कि समाजवाद ध्वस्त हो गया है। समाजवाद अपने साथ बहुत बड़ी उम्मीद और भरोसा लेकर आया था। 1917 की रूसी क्रांति ने एक नई सभ्यता को जन्म दिया था। यह 70 वर्ष तक कायम रही। हमारे देश के रवीन्द्रनाथ, शरतचंद्र, प्रेमचंद, सुब्रमण्यम भारती, नजरूल, सुभाषचंद्र, भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर पश्चिमी देशों के आइन्स्टीन, बर्नार्ड शा और रोमां रोलां तक-सभी ने रूसी क्रांति और समाजवाद की प्रशंसा की थी। इन महान विभूतियों में से कोई भी कम्युनिस्ट नहीं था। मजदूर वर्ग की नई सभ्यता में छंटनी नहीं थी, कोई बेरोजगार नहीं था। प्रत्येक के लिए रोजगार की गारंटी थी। सभी को मुफ्त चिकित्सा सेवा और शिक्षा उपलब्ध थी। महिलाओं को सच्चे अर्थों में बराबरी का दर्जा हासिल था। बच्चों और बुजुर्गों का समाजवादी राज्य द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता था। समाजवाद तेजी से प्रगति कर रहा था। लेकिन उसी समाजवाद को समाजवाद के अंदर रह गये पूंजीवाद के द्वारा गुप्त षड़यंत्र का जाल बुन कर तबाह कर दिया गया जिसको बाहर से साम्राज्यवादी-पूंजीवादी ताकतों द्वारा मदद दी गई और प्रोत्साहन दिया गया। मार्क्स से लेकर लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग और कॉमरेड शिवदास घोष सभी मार्क्सवादी हस्तियों ने इस षड़यंत्र के बारे में चेतावनी दी थीं लेकिन समाजवाद की विस्मयकारी प्रगति ने सोवियत यूनियन और चीन के नागरिकों के अंदर एक तरह की आत्म-संतुष्टि और अहंवादी मानसिकता का संचार कर दिया था। वे खतरे के बारे में सतर्क नहीं थे। कॉमरेड शिवदास घोष ने दर्शाया था कि हालांकि अर्थव्यस्था में निजी मालिकाने का खात्मा हो गया लेकिन सोवियत लोग निजी संपत्ति जनित मानसिकता से मुक्त नहीं हुये थे। इस मानसिक जटिलता का उन्मूलन करने के लिए एक सचेत संघर्ष छेड़ना निहायत ही जरूरी था। महान स्टालिन अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर इस खतरे को समझ गये थे और अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद संशोधनवादी उभार ने प्रतिक्रांति कर दी और समाजवाद को ध्वस्त कर दिया। जब तक समाजवाद कायम रहा, विश्व पूंजीवाद-साम्राज्यवाद को वस्तुतः कोने में धकेल दिया गया था।

आज समाजवादी खेमा अस्तित्व में नहीं है। साम्राज्यवादियों-पूंजीवादियों के बेलगाम बेरहम शोषण का शिकार हो रहे हैं दुनियाभर के उत्पीड़ित लोग। दूसरी तरफ तमाम पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश आणविक हथियारों सहित अपने शस्त्रागार के घातक हथियारों को बढ़ा रहे हैं। ये तमाम पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश भारी मात्रा में राजकोषीय ऋण ले रहे हैं। मितव्ययता के नाम पर पूंजीवादी-साम्राज्यवादी शासकगण सुनियोजित तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में बजट आबंटन में कटौती कर रहे हैं। लेकिन मिलिट्री बजट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पूंजीवादी-साम्राज्यवादियों को युद्ध, हथियारों और सेना की जरूरत है। वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध लगा रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही अमेरिका-ब्रिटेन गठजोड़ ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास जनसंहारक हथियार होने का झूठा बहाना बना कर इराक पर आक्रमण करके उस पर कब्जा जमा लिया। आज तक भी वे अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दे पाये हैं। अब वे कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की थी। क्या मजाक है? एक 'गलती' की वजह से उन्होंने एक देश को खण्डहर में तब्दील कर दिया और फिर भी मानवता पर किये गये ऐसे एक जघन्य अपराध के लिए उन्हें कोई पछतावा या संताप नहीं है। 1954 में जब मिस्र की सरकार ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्यवादियों ने संयुक्त रूप से मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। सोवियत सरकार ने चेतावनी जारी कर दी '12 घण्टे के अंदर अपनी फौज हटा लो। नहीं तो हम लंदन और पैरिस दोनों पर बमबारी करेंगे।' उन्होंने ब्रिटिश और फ्रेंच नागरिकों को बताया, 'हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी सरकार ने मिस्र पर आक्रमण किया है। आप इसे रोकिये।' 6 घण्टे के अंदर अमेरिका समर्थित ब्रिटिश-फ्रेंच फौजों को पीछे हटना पड़ा था। आज अमेरिकी साम्राज्यवादियों और उनके सहयोगियों ने इराक को तबाह कर दिया है।, अफगानिस्तान और लीबिया को ध्वस्त कर दिया है। अब वे सीरिया की घेराबंदी कर रहे है। यदि सोवियत समाजवाद कायम रहता तो क्या वे ऐसा करने का साहस कर सकते थे? बिन लादेन, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट को किसने पैदा किया है? अमेरिकी साम्राज्यवाद की सरपरस्ती में साम्राज्यवादियों ने पैदा किया है। इन आतंकवादी संगठनों का अपना कोई देश या अपनी राजसत्ता नहीं है। फिर इन्हें हथियार कहां से मिल रहे हैं? उन्हें हथियारों की आपूर्ति कौन कर रहा है? कैसे एक के बाद एक हमलों को अंजाम देने के लिए इतनी भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार आईएसआईएस को प्राप्त हो रहे हैं? ये साम्राज्यवादी ताकतें ही हैं जो उन्हें तमाम मिलट्री साजो-सामान मुहैया करा रही हैं। सीरिया में छद्म युद्ध चल रहा है। एक तरफ है अमेरिकी साम्राज्यवादी दूसर तरफ है रूस जो प्रतिक्रांति के बाद साम्राज्यवादी शक्ति बन गया है। जहां रूस सीरिया का समर्थन कर रहा है वहीं अमेरिकी साम्राज्यवादी उस देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। एक और युद्ध का खतरा कोरियाई प्रायद्वीप में पैदा किया जा रहा है। अमेरिकी युद्धपोत उत्तरी कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। उस देश को तबाह करने के लिए। प्रतिक्रांति के बाद चीन भी एक पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश है। चीनी राष्ट्रपति किसी भी समय में युद्ध छिड़ जाने के बारे में अपनी सशस्त्र सेना को सावधान कर रहे हैं और तैयार रहने के लिए बता रहे हैं। अतः एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। या तो यह एक स्थानीय युद्ध हो सकता है। नहीं तो एक बड़े पैमाने का युद्ध भी हो सकता है। साम्राज्यवादियों-पूंजीवादियों को अपने शस्त्रों के भण्डार को खपाने की जरूरत है जिन्हें वे अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण के हिस्से के रूप में निर्मित करते रहे हैं। इसलिए शस्त्र व्यापार को विस्तारित करने के साथ-साथ दूसरे देशों पर आधिपत्य जमाने के लिए भी उन्हें युद्ध की जरूरत है। इस प्रकार एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

ऐसी स्थिति में, मजदूर-किसानों-गरीब मेहनतकश जनता को कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों के आधार पर एकजुट करते हुए हम वर्ग-संघर्षों और जनसंघर्षों को विकसित कर रहे हैं। हम शासक भारतीय पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जो पहले ही साम्राज्यवादी चरित्र अख्तियार कर चुका है, फासीवाद थोप रहा है और अपने पूंजीवादी साम्राज्यवादी मंसूबे आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवादियों के साथ हाथ मिला रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद-जियोनिस्ट इस्राइल-भारतीय साम्राज्यवाद-जापान और आस्ट्रेलिया ने आर्थिक संधियाँ की हैं और रूस तथा चीन का मुकाबला करने के लिए मिलट्री गठजोड़ कायम किया है। इसलिए भयावह दिन मुंह बाये खड़े हैं। लोगों को एकजुट हो जाने और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट संघर्ष छेड़ने की जरूरत है।

### इस बार भी सीपीआई(एम) ने घोंपा वामपंथी एकता की पीठ में छुरा

मैंने पहले ही कहा है कि हम वामपंथी एकता चाहते हैं। सीपीआई(एम) ने ही एकता तोड़ी थी। एकबार पुनः वे एकता के लिए हमारे पास आये थे। हमने सकारात्मक उत्तर दिया। साम्राज्यवाद-विरोधी और साम्प्रदायिकता-विरोधी मुद्दों को केन्द्र करके कुछ संयुक्त कार्यक्रम भी संगठित किये गये थे। अचानक बिना हमें कुछ बताये सीपीआई(एम) ने हमारे साथ एकता को तोड़ दिया और सिर्फ तुच्छ चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। सीपीआई(एम) कार्यकताओं को सोचना चाहिए कि किस हद तक उनकी पार्टी वोट आधारित हो गई है कि ऐसा एक काम वो बिना किसी दुविधा के कर सकी। क्या कांग्रेस एक जनवादी ताकत है? आपातकाल किसने थोपा था? किसने मीसा, टाडा और आफ्स्पा (एएफएसपीए) जैसे काले कानून लगाये थे? क्या ऐसा है कि साम्प्रदायिक दंगे बीजेपी के शासनकाल में ही भड़काये गये हैं? क्या कांग्रेस शासनकाल के दौरान भागलपुर बिहार में, राउरकेला उड़ीसा में और नेल्ली आसाम में दंगे नहीं भड़के थे? क्या दिल्ली में सिखों का कत्लेआम नहीं हुआ था? अब डेमोक्रेसी को बचाने और साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के नाम पर सीपीआई(एम) उसी कांग्रेस में दोस्त तलाश रही है। असल में, यह एक चुनावी गठजोड़ है और घोर अवसरवाद के सिवा और कुछ नहीं है। इस तरीके से सीपीआई(एम) ने उस वामपंथी एकता की पीठ में छुरा घोंपा जो धीरे-धीरे साकार हो रही थी। हम अभी भी तैयार हैं। हम उनसे यही चाहते हैं कि वे कांग्रेस से नाता तोड़ें और जनआंदोलन के रास्ते पर आ जायें। हम वोट

(शेष पृष्ठ 7 पर)

# म.प्र. में लड़ाई जारी रखने का किसानों ने लिया संकल्प

**अशोकनगर ( म.प्र. ) :** प्रदेश की वामपंथी पार्टियों ने गत दिनों शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने पर अशोकनगर में इनके कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने की कड़ी भर्त्सना की। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह है कि इन 20 कार्यकर्ताओं को तब गिरफ्तार किया गया जब वे मंदसौर गोलीकांड में शहीद हुए किसानों की स्मृति में एसयूसीआई(सी) द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग ले रहे थे। गिरफ्तार किये गये नागरिकों में एसयूसीआई(सी) के जिला सचिव सचिन जैन सहित अधिकांश नौजवान हैं। सीपीआई(एम) के राज्य सचिव बादल सरोज, सीपीआई के राज्य सचिव मण्डल सदस्य शैलेन्द्र कुमार शैली, एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव प्रताप सामल और सीपीआई (माले) लिबरेशन के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र सिंह चौहान ने पुलिस-प्रशासन की इस बेहूदी कार्यवाई एवं इन गिरफ्तारियों को भाजपा सरकार के बढ़ते अलगाव से उपजी तानाशाही का प्रतीक बताया।

वामदलों ने गिरफ्तार किये गए सभी कार्यकर्ताओं की अविलंब रिहाई और आइन्दा सार्वजनिक आयोजनों के साथ इस तरह के अलोकतांत्रिक बर्ताव पर रोक लगाने की मांग की।

16 जून को जेल से छूटने पर इनका लोगों द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया गया और फूलों के हार पहनाये गये। वहां मौजूद लोगों ने इन नेताओं की अगुआई में आन्दोलन जारी रखने का संकल्प लिया।

# सहारनपुर, गुड़गांव, जेवर व मंदसौर आदि कांडों पर जतायी चिंता

**जोया ( उ.प्र. ) :** गुड़गांव व जेवर में हुए बलात्कार कांड और सहारनपुर में बेकसूर लोगों पर हुए अत्याचार के खिलाफ एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ताओं ने जिला इंचार्ज कॉ. शील कुमार के नेतृत्व में 12 जून को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी जनपद अमरोहा की मार्फत भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि शांतिपूर्ण जनआन्दोलनों में पुलिस दखल बंद किया जाये। सहारनपुर कांड के दोषियों को सजा दी जाये। गुड़गांव व जेवर में बलात्कार के दोषियों को उदारहरणमूलक कठोर सजा दी जाये। बेकसूरों पर ढाये जा रहे जुल्म पर रोक लगाई जाये। कानून-व्यवस्था को दुरस्त किया जाये। मंदसौर में किसानों के हत्यारों को सजा दी जाये।

प्रदर्शन में देवराज सिंह, धर्मपाल सिंह, बलबीर सिंह, राजेन्द्र सिंह एडवोकेट, गंभीर सिंह, नरेन्द्र सिंह, दिग्गराज सिंह, महेन्द्र सिंह, पवन, मूलचंद सिंह, नौबहार आदि शामिल थे।

## कॉ. प्रभास घोष का भाषण

( पृष्ठ 6 का शेष )

के लिए नहीं, आंदोलन के लिए एकता चाहते हैं। हम देशभर में जुझारू वामपंथी आंदालन चाहते हैं।

हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे अविभाजित बंगाल मे हुए जोशीले संघर्ष के शानदार अतीत को याद करें। एक समय देश में कहा जाता था कि, 'बंगाल जो आज सोचता है, भारत कल सोचता है।' अविभाजित बंगाल ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया था। इस बंगाल ने राममोहन, विद्यासागर, विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ, शरतचन्द्र, नजरूल और देशबंधु चित्तरंजन, सुभाषचंद्र, खुदीराम जैसे अनेकों महान हस्तियों और क्रांतिकारियों को जन्म दिया था। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चन्द्र बोस, सत्येन बोस और मेघनाथ शाह जैसे विख्यात वैज्ञानिक भी यहां जन्में थे। उस समय साहित्य, दर्शन, विज्ञान और ज्ञान की तमाम अन्य शाखाओं में बंगाल एक बहुत प्रतिष्ठित स्थान रखता था। क्या वही बंगाल अब साम्प्रदायिक आरएसएस-बीजेपी और फासीववाद के झण्डे को उठायेगा? या संघर्ष के अपने शानदार अतीत की परम्परा को कायम रखते हुए बंगाल फासीवाद के खिलाफ, पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के खिलाफ समाजवाद के झण्डे को बुलंद करेगा? जनता के सामने हमारा यही आवेदन है।

कृपया जनसंघर्ष कमेटियों का निर्माण करिये, गांवों, कस्बों, मजदूर बस्तियों और किसान क्षेत्रों में छात्रों और नौजवानों की संघर्ष कमेटियों का निर्माण करिये। वहां जन संगठनों का निर्माण करिये। जीवन की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर आंदोलन विकसित करिये। साथ ही साथ महापुरुषों और पथ प्रदर्शकों की जन्म और मृत्यु वार्षिकियां उचित सम्मान के साथ मनाइये। पूंजीवादी-साम्राज्यवादी शासकगण और उनके सेवादार चाहते हैं कि नौजवान और छात्र शराब में डूबे रहें, यौन विकृति में फंसे रहें, स्त्री शरीर की चर्चा में पाशविक आनंद लेते रहे, हिन्दुत्व की महिमा गाते रहें और गोवध के खिलाफ नारे उठाते रहें। वे चाहते हैं कि लोग राममोहन, विद्यासागर, रवीन्द्रनाथ, शरतचंद्र, नजरूल, प्रेमचंद, सुब्रमण्यम भारती, सुभाष चन्द्र, भगतसिंह, ज्योतिबाराव फुले, खुदीराम को भूल जायें। इस प्रकार वे शानदार अतीत से वर्तमान पीढ़ी का संबंध विच्छेद कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन महान विभूतियों की वर्षगांठ मनायें, अपने हृदय में उन्हें स्थान दें। कॉमरेड शिवदास घोष ने सिखाया है कि सर्वहारा क्रांतिकारी का चरित्र अर्जित करने के लिए हमें इन महापुरुषों और शहीदों के जीवन संघर्षों से मिली शिक्षाओं को निचोड़ लेना होगा और तब उच्च सर्वहारा संस्कृति हासिल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने हमारा आह्वान किया था उनके उच्च गुणों को आत्मसात करने के लिए आजादी आंदोलन के दौरान उनके द्वारा प्रतिबिंबित महान सांस्कृतिक स्तर को हासिल करने के लिए। क्योंकि जैसाकि उन्होंने बताया था हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं। हमारे आजादी आंदोलन के दौरान जो उच्च सांस्कृतिक स्तर हासिल हुआ था उसकी निरंतरता को बरकारा रखने में हम नाकाम हुए हैं। हमें उसी कड़ी को फिर से जोड़ना होगा। हमें अतीत के तमाम महापुरुषों से शिक्षाएं ग्रहण करनी होंगी। इसलिए कृपया इस आंदोलन को विकसित करिये। और मैं आप सभी से जोरदार आग्रह करूंगा कि बच्चों को बचाइये। उन्हें बिगाड़ा जा रहा है। कक्षा चार और पांच के कुछ छात्र शराबी बन रहे हैं, सड़ी-गली यौन विकृत बातों में शामिल हो रहे हैं और यहाँ तक कि सैक्स में लिप्त हो रहे हैं। यह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह एक भंयकर खतरा है। खेलों और डिबेटों का आयोजन करिये। अतीत के महापुरुषों के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चाएं आयोजित करिये। रवीन्द्रनाथ, शरतचंद्र, नजरूल, सुभाषचंद्र, भगतसिंह, ज्योतिबाराव फूले को पढ़ने, जानने-समझने की जिज्ञासा बच्चों में जगाइये। ये काम इतवार की सुबह या छुट्टी के दिन किया जा सकता है। उनमें स्वस्थ्य संस्कृति का रोपण करिये। विभिन्न बस्तियों में एक नया सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ दीजिए। हमारी पार्टी का यही आह्वान है।

अत: एक तरफ जन आन्दोलनं और वर्ग संघर्ष गठित करिये, संघर्ष कमेटियाँ और स्वंयसेवक दस्ते बनाइये जबकि दूसरी ओर सांस्कृतिक आंदोलन छेड़िये, बच्चों को बचाइये। इसी के साथ समाप्त करता हूँ।

इन्कलाब जिंदाबाद!
एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जिंदाबाद!
महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष
चिंतन जिंदाबाद!

● ● ●

# म.प्र. में रासुका लगाने के खिलाफ प्रदर्शन

**भोपाल( म.प्र. ) :** 19 जून के मध्यप्रदेश राजपत्र द्वारा प्रदेश के जिला दण्डाधिकारियों को 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अधिकृत करने के आदेश के खिलाफ एस.यू.सी.आई (कम्युनिस्ट) व सी.पी.आई (एम) की जिला इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय बोर्ड आफिस चौराहे पर 27 जून को एक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में एस.यू.सी.आई (सी) के जिला सचिव कॉ. जगदीश बरई ने कहा, जबकि मध्यप्रदेश के लोग प्रदेश सरकार द्वारा किसान आंदोलन पर गोली चलाने जिसमें 6 किसानों की मौत हुई, इस घोर जनविरोधी कार्य से काफी दुखी हैं एवं सरकार से रूष्ट भी हैं। साथ ही देश में जीएसटी लागू हो जाने के कदम पर लोग काफी आशंकित व चिंतित हैं। उस समय राज्य सरकार द्वारा रासुका जैसे काले कानून लागू करना घोर जनविरोधी है। उन्होंने इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। सीपीआई (एम) के जिला सचिव प्रसून भट्टाचार्य ने कहा कि देश में आपातकाल लगाने के 42वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में जब आपातकाल लगने से हुई लोगों की परेशानियों पर लम्बे ब्यौरे प्रस्तुत किये वहीं उन्हीं के मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने ठीक उसी समय प्रदेश में रासुका लागू कर दिया है।

सरकार के इस घोर जनविरोधी फासीवादी आदेश की प्रदर्शन में काफी निंदा हुई एवं इसे तुरंत वापस लेने की मांग की गई। साथ साथ प्रदर्शन स्थल पर इस आदेश की प्रतियां भी जलाई गई।

# मंदसौर गोलीकांड की निंदा की

**दुर्ग ( छ.ग. ) :** मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में भाजपा सरकार द्वारा आंदोलनकारी किसानों पर, गोली चलाकर 5 किसानों की हत्या कर दी गई जो आंदोलनकारी किसानों पर घोर जुल्म, अन्याय और घोर बर्बतापूर्ण कार्य है जो काफी निन्दनीय है और इस अमानवीय घटना ने सरकार का किसान-विरोधी, तानाशाहीपूर्ण व अलोकतांत्रिक चेहरा बेनकाब कर दिया है। इस बर्बर घटना के खिलाफ 14 जून को अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की ओर से पुराना बस स्टैण्ड, दुर्ग (छ.ग.) में प्रदर्शन व श्रद्धांजली सभा की गई और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि इस गोलीकांड के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। मध्यप्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। किसानों को उसकी लागत में 50 प्रतिशत और जोड़कर समर्थन मूल्य तय किया जाए। किसानों का सारा उत्पादन लाभकारी मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदा जाए। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए। खाद व कीटनाशकों की कीमतों में मुनाफाखोरी बंद करो व बिचौलियों के गोरखधंधे व बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करो। बिजली व सिंचाई की व्यवस्था करो। कर्ज के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार को कम से कम 5 लाख मुआवजा और एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए।

# सेमिनार आयोजित

**घाटशिला ( झारखण्ड ) :** -मोदी सरकार के तीन साल' विषय पर यहां एआईडीएसओ द्वारा 17 जून को एक सेमिनार किया गया। इसके मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) के झारखण्ड राज्य कमेटी सदस्य कॉ. सुमित राय थे।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication : July 5, 2017

सर्वहारा दृष्टिकोण

7 से 21 जुलाई, 2017

# मंदसौर कांड के दोषियों को कड़ी सजा देने और ओडिशा में सभी कृषि कर्ज माफ करने की मांग को लेकर राजभवन पर विशाल प्रदर्शन

**भुवनेश्वर : किसानों के हत्यारों को सजा देने और कर्जामाफी की मांग करते हुए एआईकेकेएमएस के कार्यकर्ता**

**भुवनेश्वर (ओडिशा) :** म.प्र. में किसानों पर गोली चलाने के दोषी पुलिस अधिकारियों व राजनेताओं को कड़ी सजा देने, ओडिशा में सभी कृषि कर्ज माफ करने, किसानों की फसलों के लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को कम से कम 5000 रुपये मासिक बुढ़ापा पेन्शन देने, आत्महत्या करने को मजबूर हुए किसान के परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग पर ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) की ओर से 19 जून को राजभवन पर विशाल प्रदर्शन किया गया। एआईकेकेएमएस के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. उद्धव जाना की अध्यक्षता में एक सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के राज्य सचिव कॉ. रघुनाथ दास ने किसानों की जायज मांगों को हासिल करने के लिए जोरदार किसान आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने बीजेपी की केन्द्र सरकार और साथ ही बीजेडी की राज्य सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ आन्दोलन तेज करने की किसानों से अपील की। सभा को संगठन के उपाध्यक्ष कॉ. सदासिव दास और जिला सचिवों ने भी संबोधित किया।

किसान संगठन की ओर से ओडिशा के राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया गया।

# बेरोजगारी-विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया एआईडीवाईओ का 51वां स्थापना दिवस

**दिल्ली : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. अमरजीत**

ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाईजेशन (एआईडीवाईओ) की दिल्ली राज्य कमेटी की ओर से संगठन का 51वां स्थापना दिवस 'बेरोजगारी-विरोधी दिवस' के रूप में 2 जुलाई को दिल्ली के सीमापुरी के गोल चक्कर पर मनाया गया। सभा में दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं व आम नागरिकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरूआत क्रांतिकारी गीतों से हुई। शकूरपुर इकाई की ओर से 'अंधेर नगरी' नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन की राज्य अध्यक्षा प्रकाश देवी ने की।

सभा को सम्बोधित करते हुए संगठन के दिल्ली राज्य सचिव अमरजीत ने कहा कि आज बेरोजगारी की समस्या इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि एक चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए लाखों उच्च डिग्रीधारी युवा आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या का समाधान केवल समाजवाद में ही संभव हैं, अत: युवाओं को पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति को सफल बनाने हेतु मजबूत युवा आंदोलन निर्मित करना होगा।

राज्य उपाध्यक्ष कॉ. प्रभाष ने युवाओं को अश्लीलता व नशाखोरी के खिलाफ जोरदार आंदोलन निर्मित करने का आह्वान किया। अध्यक्षीय भाषण के बाद जोरदार नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

कार्यक्रम का संचालन राज्य कमेटी के सचिवमण्डल के सदस्य कॉ. हरीश ने किया।

**संगठन के स्थापना दिवस पर आयोजित सभा में उपस्थित युवा**

# जीएसटी का विरोध ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

सेवाओं के करों में इजाफे के फलस्वरूप महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी।

सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कमिटी सदस्य मणिकांत पाठक ने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने घनीभूत होते संकटों से निजात पाने के लिए जनता पर यह बर्बर आर्थिक हमला बोल रही है। जीएसटी की इस नयी कर प्रणाली से एकाधिकार पूंजीपतियों व कारपोरेट घरानों को फायदा होगा, जबकि छोटे व खुदरा व्यापारी तबाह हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से केन्द्र सरकार के हाथों में राजस्व का संकेन्द्रण बढ़ेगा और राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। इसके चलते केन्द्र के हाथों में आर्थिक ताकतों का जोरदार केन्द्रीकरण होगा, जो देश को प्रशासनिक फासीवाद की ओर ले जायेगा।

सभा को जिला कमिटी सदस्य सूर्यकर जितेन्द्र, राजकुमार चौधरी, अनामिका आदि ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने लोगों से जीएसटी के खिलाफ ताकतवर आंदोलन निर्मित करने की अपील की।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503